Shri Samar Guha: In the statement made by the External Affairs Minister he has stated quoting the Morning News, Dacca that the priest was assassinated by some dacoits. It is not correct. Secondly, it is stated that the government have not received any information regarding the reported destruction of the ancient Buddhist Vihar. It is also not correct. With your permission, I will place on the Table a paper called Jagaran....

Mr. Deputy-Speaker: Whatever your information is, you put a question on the basis of that information. You are permitted to put a question. I will not allow the other documents to be placed on the Table of the House.

Shri Samar Guha: The question is (a) whether with a view to work out two objectives of the Pindi Plan, firstly to make infiltration route of the Naga and Mizo hostiles to their training camps in the Chittagong Hill Tract area safe and secure and secondly to mischievously confuse the vigorous autonomy movement of the East Pak. people against Pindi domination by spreading communal passion atrocities on Buddhist minorities had been committed and recently intensified by Pro-Ayub elements to squeeze out the Chakma people totally from this strategic area of Hill Chittagong and (b) whether the Chakma community of the Chittagong Hill Tract Area which is situated adjacent to Assam and Tripura, constituted 97 per cent of the local population at the time of partition and whether nearly 37,000 Chakma have been squeezed out since partition....

Mr. Deputy-Speaker: It will be difficult for the Minister to follow so many questions and then answer them. I am unable to follow the question.

Shri Samar Guha: One man, one question... and (c) whether the Government of India will make an effort to mobilise world opinion, particularly of the Buddhist countries at present, against politically motivated atrocities engineered by Pro-Ayub elements on the Buddhist and other minorities of East Pakistan?

Mr. Deputy-Speaker: The hon. Minister may answer one question.

Shri M. C. Chagla: May I take the last question which is a very important question: whether we mobilised world public opinion against what is happening in Pakistan. We have informed all the Buddhist countries of Southeast Asia about what is happening to the Buddhist minority in Pakistan. By a curious irony Pakistan has decided to call an international Buddhist conference in Dacca in 1968. We have drawn the attention of the Buddhist countries that this is merely window dressing and we have pointed out to them how the Buddhist minority has been treated. As far as we are concerned, we have mobilised public opinion.

Mr. Deputy-Speaker: We will take up the half-an-hour discussion.

17.59 hrs.

SCARCITY OF SUGARCANE*

श्री प्रकाश वीर शास्त्री (हापुड़) : उपाध्यक्ष जी, गन्ने की कीमत और चीनी की कमी से संबंधित अपनी चर्चा को प्रारम्भ करते हुए खाद्य मंत्री से आपके द्वारा मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रश्न को ले कर संसद में कई बार प्रश्नों के रूप में और कई बार चर्चाओं के रूप में यह बात सामने आई है लेकिन दुख है कि अभी तक इस का कोई सन्तोषजनक समाधान नहीं हो सका है। 1965–66 में इस देश में लगभग 32 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ था। तब ऐसा लगता था कि देश चीनी के संबंध में आत्म-निर्भर हो जाएगा क्योंकि जहां तक भारतवर्ष में चीनी की खपत का संबंध है लगभग 28 लाख टन की ही हमारी आवश्यक-

*Half-an-hour discussion.

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

ता थी। विदेशों को भी तब भारत सरकार ने अपना चीनी का बाजार बनाने के लिए कुछ निर्यात प्रारम्भ किया जिससे शायद चौदह पन्द्रह करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा का अर्जन भी भारत को हुआ। लेकिन सरकार की अदूरदर्शी नीति का परिणाम यह हुआ कि 1966-67 में चीनी का उत्पादन 32 लाख टन से घट कर केवल 21 लाख टन रह गया। इससे खाने के लिए भी जो देश की अपनी खपत थी उस में सात लाख टन की कमी हो गई। और विदेशी बाजार भी हमारे हाथों में रह पायेगा, यह भी संदिग्ध हो गया है।

18 hrs.

सरकार की गलत नीतियों का क्या दुष्परिणाम हुआ है, इसका एक उदाहरण यह है कि उत्तर प्रदेश में गन्ने को उपज धीरे-धीरे कम होती चली जा रही है। सरकार द्वारा दिये गये आंकड़े स्पष्ट रूप से यह बताते हैं कि 1965 में अकेले उत्तर प्रदेश में 25 लाख एकड़ जमीन में गन्ना बोया जाता था, लेकिन सरकार की गलत नीतियों के कारण 1966 में गन्ने का क्षेत्र घट कर 20 लाख एकड़ रह गया और इस समय 1967 में केवल 15 लाख एकड़ जमीन में गन्ना बोया गया है। इस से आप अनुमान लगा सकते हैं कि अगर सरकार ने गन्ने की कीमत के संबंध में कोई बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय नहीं लिया, तो आगे चल कर स्थिति और कितनी भयावह होने जा रही है। अगर पिछले साल जैसी स्थिति रही और सरकार ने समय रहते गन्ने की कीमत के संबंध में कोई घोषणा नहीं की, तो मेरा अनुमान है कि इस साल सारे देश में कुल मिला कर अधिक से अधिक दस या बारह लाख टन चीनी बन पायेगी।

इसका क्या दुष्परिणाम होगा? सब से पहला नुक्सान तो यह होगा कि सरकार को चीनी के करों द्वारा लगभग चालीस, पचास करोड़ रुपये की जो आय होती है, वह सारी आय उस के हाथों से जाती रहेगी। दूसरा नुक्सान यह होगा कि देश में आधे से अधिक चीनी के कारखाने बन्द हो जायेंगे और पचास हजार से ले कर सत्तर हजार तक मजदूर बेकार हो जायेंगे। तीसरा नुक्सान यह होगा कि एक ओर तो देश में खाने के लिए चीनी नहीं मिलेगी और दूसरी ओर विदेशी बाजार भी हमारे हाथों से जाता रहेगा। चौथा नुक्सान यह होगा कि देश में चीनी के संबंध में जो काला बाजार और चोर बाजारी चल पड़ी है, उस को स्वभाविक रूप से प्रोत्साहन मिलेगा।

18.02 hrs.

[SHRI G. S. DHILLON *in the Chair*].

इस संबंध में मैं तीन सुझाव देना चाहता हूं। गन्ने को किस कीमत पर और कहां बेचा जाये, यह निर्णय करने का अधिकार गन्ने के उत्पादक किसान को दिया जाये और सरकार को इस के बीच में नहीं आना चाहिए। दो, चीनी पर से कंट्रोल हटा दिया जाये। तीन, अगर सरकार गन्ने की कीमत निर्धारित भी करती है, तो वे इस प्रकार के लगते-भिड़ते भाव हों कि गुड़, खंडसारी और चीनी मिलों को जो गन्ना दिया जाये, उस के भावों में कोई विशेष भेद नहीं होना चाहिए। अगर सरकार इन व्यावहारिक सुझावों को मान लेती है, तो मेरा निम्बित मत है कि इस साल ही कम से कम पच्चीम साख टन तक चीनी का उत्पादन हो सकता है और इस संबंध में देश के सामने जो गम्भीर संकट खड़ा हो गया है, वह टल सकता है।

मेरे कुछ मित्र कहेंगे कि अगर चीनी पर से कंट्रोल हटा दिया जाये, तो चीनी के दाम और ऊंचे चले जायेंगे, लेकिन प्रश्न यह है कि

आज चीनी के दाम बाजार में क्या हैं। कंट्रोल हटाने का परिणाम यह होगा कि काले बाजार में चीनी के दाम कम हो जायेंगे—वे ऊपर जाने वाले नहीं हैं आप जानते ही होंगे कि आज चीनी में किस किस प्रकार की मिलावट की जाती है। आप ने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा कि चीनी में खेतों में डाली जाने वाली खाद तक भी मिलाई जाने लगी है। अगर चीनी पर से नियंत्रण हटा दिया जाये, तो इस स्थिति में सुधार हो सकता है।

मैं यह भी बताना चाहता हूं कि केवल उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा और पंजाब की राज्य सरकारों ने ही नहीं, बल्कि जिन अन्य राज्यों में भी गन्ने की पैदावार होती है, उन सभी ने केन्द्रीय सरकार से कई बार अनुरोध किया है कि गन्ने की कीमत बढ़ाई जाये, लेकिन केन्द्रीय सरकार अपने कानों में तेल डाले हुए पड़ी है और कहती है कि समय आने पर हम इस बारे में घोषणा करेंगे, मानो कोई इस से भी अधिक विषम स्थिति उत्पन्न होगी, जब सरकार इस संबंध में विचार करेगी।

आपको यह जान कर दुख होगा कि 1947–48 में गन्ने का भाव दो रुपये मन था और पिछले साल, जब कि महंगाई आसमान को छू रही है और सब वस्तुओं के दाम बढ़ गए हैं, उसका भाव 2 रुपये 6 आने से ले कर 2 रुपये 8 आने तक पहुंचा। क्या सरकार बतायेगी कि क्या इन बीस सालों में बाकी चीजों के दाम भी इसी अनुमापात से बढ़े हैं ? जयदि नहीं, तो फिर गन्ने के उत्पादन, के गले पर क्यों विशेष रूप से छुरी रखी जाती है और उस के साथ यह अन्याय क्यों किया जाता है ?

आप को यह भी जान कर कष्ट होगा कि पिछले साल जब कि गन्ने का भाव ढाई रुपये मन था, तब गन्ने के ऊपर के जो हरे पत्ते, हरे अगौले, बैलों और पशुओं के खाने के काम आते हैं, उनका भाव पौने तीन रुपये मन था। आज सूखी लकड़ी का मन पांच रुपया मन है और किसान ठंड और पाले में खड़े हो कर जो गन्ना तैयार करता है, उस का भाव ढाई रुपये मन है। क्या यह सरकार का न्याय है ? जब लगान में वृधि हो गई है, सिचाई की दरें बढ़ गई हैं और खाद के दाम बढ़ गए हैं, तब गन्ने की कीमत न बढ़े यह किसान के साथ सरासर अन्याय है।

मैं आप के माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूं कि गन्ने की कीमत के संबंध में जो सिद्धांत और नियम इंडोनेशिया और मैक्सिको की सरकारों ने अपनाए हुए हैं, उसी प्रकार के सिद्धान्त भारत सरकार को भी अपनाने चाहिए। मैक्सिको गवर्नमैंट का नियम है कि जब किसान गन्ना ले कर मिल के दरवाजे पर पहुंचता है, तो गन्ने का पचास प्रतिशत मूल्य उस को दे दिया जाता है। बाद में जब चीनी बाजार में आती है, तो उस के अनुपात से पचास प्रतिशत मूल्य किसान को दे दिया जाता है। इस से किसान को संतोष होता है।

श्री रफी अहमद किदवई जब भारत सरकार के कृषि मंत्री थे, तो इन्होंने इसी आधार पर यह नारा लगाया था : जितने रुपये मन चीनी, उतने आने मन गन्ना। उसके अनुसार अगर आज चीनी का भाव अस्सी रुपये मन है, तो गन्ने का भाव पांच रुपये मन होना चाहिये। सरकार एक ओर तो यह चाहती है कि देश में चीनी और गन्ने का उत्पादन बढ़े, लेकिन दूसरी ओर वह किसान के साथ अन्याय भी करना चाहती है, जिस से किसान को किसी प्रकार का प्रोत्साहन न मिले।

मैं यह सुझाव भी देना चाहता हूं कि जब किसान गन्ना लेकर मिल पर जाता है, तो उसको नगद दाम के साथ साथ उसका कुछ भाग चीनी के रूप में देना चाहिये। किसान गन्ने का मूल उत्पादक है और उसके के गन्ने की चीनी बनती है, लेकिन अपने

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

लड़के-लड़की के विवाह के अवसर पर जब उसको एक बोरा या दस, बीस सेर चीनी के लिए तहसीलदार या कलक्टर के दरवाजे पर जाना पड़ता है, तो उस समय उसको आश्चर्य होता है कि गन्ना तो मैं पैदा करता हूं, लेकिन चीनी के लिए मुझे दर दर मारा मारा फिरना पड़ता है। इस लिए सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि किसान को अपने गन्ने के नकद दाम का कुछ निश्चित प्रतिशत चीनी के रूप में दिया जाये।

अन्त में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब कि यह सदन बराबर तीन महीने से कृषि मंत्री के कानों में यह आवाज दोहराता रहा है कि गन्ने का दाम बढ़ाया जाये, और चीनी पर से कंट्रोल हटाया जाये तो मुझे विश्वास है कि इस चर्चा के बाद सरकार इस प्रश्न को और ज्यादा नहीं टालेगी, देश की स्थिति को और नहीं बिगड़ने देगी और गन्ने के भाव को श्री रफ़ी अहमद किदवई के इस सिद्धांत के अनुसार तय कर देगी कि जितने रुपये मन चीनी का भाव है, उतने आने मन गन्ने का भाव होना चाहिये।

श्री रघुवीर सिंह शास्त्री (बागपत): श्रीमन्, चीनी मिलों के मालिक और उनकी ऐसोसियेशन बराबर गवर्नमेंट को यह कह रही है कि गन्ने का मूल्य बढ़ाना चाहिये। किसान की तरफ से भी बाकायदा यह आवाज उठाई जा रही है कि उसके खून और पसीने से पैदा की गई उपज को सूखी लकड़ी और दूसरी फ़िजूल चीजों से भी कम कीमत पर खरीदा जा रहा है और उसके साथ इससे ज्यादा अन्याय नहीं हो सकता है।

मेरी समझ में नहीं आता कि जब मिल मालिक और किसान दोनों इस बात पर सहमत हैं कि गन्ने का मूल्य बढ़ाया जाये, तो फिर गन्ने का मूल्य क्यों नहीं बढ़ाया जाता है और सरकार उस पर विचार क्यों नहीं करती है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकारों ने भी गन्ने का मूल्य बढ़ाने के लिए लिखा है। यदि सरकार की ओर से यह कहा जाये कि चीनी और महंगी हो जायेगी, तो मैं कहना चाहता हूं कि वह तो अब भी महंगी बिक रही है। मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि अगर सरकार चीनी को सस्ता करना चाहती है, तो वह एक तो एक्साइज ड्यूटी को कम करे, जो कि बहुत हैवी है, और दूसरे, किसान को उसके गन्ने का अधिक से अधिक मूल्य दिलाने की व्यवस्था करे, क्योंकि वह डिजर्व करता है कि उस को अपनी उपज का सही मूल्य मिले। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि सरकार चीनी का जो मूल्य निर्धारित करती है, उसका ब्रेक-अप क्या है, अर्थात् किसान का इसमें कितना हिस्सा आता है। सरकार नौ या दस परसेंट रिकवरी पर दाम तय करती है। तो इस नौ या दस परसेंट रिकवरी में किसान का कितना हिस्सा है? किसान को मालूम होना चाहिए कि चीनी का जो मूल्य निर्धारित किया जाता है, उस के ब्रेक-अप में उसका कितना हिस्सा है, फैक्टरी-मालिक का कितना हिस्सा है, एक्साइज का कितना हिस्सा है और बेचने वाले व्यापारी का कितना हिस्सा है।

श्री ओ० प्र० त्यागी (मुरादाबाद): सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को यह ज्ञान है कि वर्तमान समय में खंडसारी और चीनी के दामों में इतना अधिक अन्तर है कि आगे आने वाले सीजन में किसान मिलों को गन्ना नहीं देंगे, बल्कि खंडसारी को देंगे, जिससे देश में चीनी का इतना भयंकर अकाल पड़ जायेगा कि जनता "त्राहि माम, त्राहि माम" कर उठेगी। अतः सरकार इस संकट को दृष्टि

में रखते हुए गन्ने के मूल्य को तुरन्त बढ़ाने या डीकंट्रोल करने का विचार रखती है ? खांडसारी वाले लोग इसी टाइम पर गन्ने का सौदा कर रहे हैं । इसलिए अगर सरकार ने गन्ने का मूल्य निर्धारित करने में या डीकंट्रोल करने में देर लगाई, तो दाम बढ़ाने पर भी वह गन्ना सरकार को नहीं मिलेगा । जो काश्तकार जिस से तय कर लेंगे खांडसारी वालों के साथ, उन को गन्ना उन्हें देना पड़ेगा, इसलिए क्या सरकार इस दिशा में कोई शीघ्र निर्णय लेने का विचार कर रही है ?

Shri Bedabrata Barua (Kaliabor): Sir, the progressive decline in the area under sugarcane shows that the cane price as it is now fixed is rather low and land is being shifted for other purposes. At the same time, I would also rather accept the proposition that even the mills are closing down—in Assam one mill has not been able to get enough supply of sugarcane—due to low recovery of sugar from the sugarcane of Bihar, U.P., Assam and other States. Will the Government consider the question of providing irrigation in these areas because irrigation has some connection with the recovery content of sugarcane? I would like to know whether the Government will provide irrigation facilities and also raise the price of sugarcane because at present it is the most uneconomic price and it would not sustain the industry. I would also like to know whether the Government is also thinking of partial decontrol because it has all its concomitants. They have said that they are considering, but I would like them to clarify the position and whether Government is thinking of devising a method for it. There are strains of high recovery cane. They are not only at the experimental stage but they have actually been obtained. I would like to know whether it is possible for the Government, while giving the incentive of higher price, to conect it with the supply to large farms of high recovery cane from where it will be supplied to all farms on the basis that if they take high recovery cane the price will be fixed at such and such a rate and there will be bonus and all that.

श्री कंवर लालगुप्त (दिल्ली सदर:) अध्यक्ष महोदय, सुपर की डिमांड 28 लाख टन है और पिछले साल हम ने 22 लाख टन पैदा किया और अगर इसी तरह से चलता रहा तो इस साल केवल 14 लाख टन हम पैदा कर सकेंगे । इतना ही नहीं इंडस्ट्रियल अल्कोहल जो मोलेसेज से बनता है उस की भी बहुत कम पैदावार है और हमें एक्सपोर्ट करना पड़ रहा है । इस का हमारे फारेन एक्सचेंज पर भी बहुत बड़ा भार पड़ रहा है । तो इस का एक ही रास्ता है कि यह जो सुगरकेन है यह खांडसारी और गुड़ की तरफ चला जाता है और केवल 30 परसेंट सुगरकेन सुगर फैक्ट्री को मिलता है, तो जब तक सुगरकेन की कीमत हम नहीं बढ़ायेंगे, फार्मर्स को ज्यादा पैसा नहीं देंगे तब तक सुगरकेन सुगर फैक्ट्री में नहीं आयेगा । इसका एक ही रास्ता है कि आप सुगर पर से कंट्रोल हटा दीजिए । आप का प्रोपोजल है 50 परसेंट हटाने का और 50 परसेंट नहीं हटाने का उस से कन्फ्यूजन होगा । वह कोई रास्ता नहीं है । या तो आप खांडसारी, गुड़ और सुगर तीनों पर कंट्रोल करिए या तीनों को डीकंट्रोल करिए । मेरा कहना यह है कि दूसरा सुझाव ज्यादा ठीक रहेगा कि आप फार्मर्स को ज्यादा इन्सेन्टिसव दीजिए, उनको ज्यादा दाम बढ़ाइए और सुगर को पूरी तरह से डीकंट्रोल करिए ।

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : अगर इस देश को भुखमरी से बचाना है और इस

[श्री रणबीर सिंह]

देश को एक शक्तिशाली देश, मजबूत देश बनाना है तो शहरों को छोड कर, सरमायेदारों को छोडकर, कारखानेदारों को छोड़ कर किसान की तरफ देखना पडेगा। किसान बावला नहीं है। किसान जाग गया है और बडा सयाना है। किसान कोई चीज नहीं देगा कारखानेदार को या सरकार को अगर उस को पूरे दाम नहीं मिलेंगे। यह दुकानदारों का काम है। किसान समझता है कि क्या नुकसान है क्या फायदा है। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं जितना गुड डालिएगा उतना ही मीठा होगा। किसानों को जितना ज्यादा पैसा देंगे उतना ही ज्यादा गन्ना वह पैदा करेंगे, उतनी ही चीनी बढ़ेगी क्योंकि जिस जमीन पर नेश्कर पैदा किया जाता है वह किसान की रुपये एक की जमीन होती है, बेहतरीन से बेहतरीन जमीन होती है, जो अच्छी से अच्छी जमीन है जिस में ज्यादा से ज्यादा खाद वह डालता है, जिस जमीन पर वह लड़ाई करता है, दिन रात पसीने से लथपथ रहता है उस में नेश्कर लगाता है। तो मेरा कहने का सिर्फ मतलब यह है कि किसान नेश्कर पैदा तब करेगा जब उस को ज्यादा कीमत आप देंगे। अगर सरकार कीमत नहीं देगी तो नेश्कर वह पैदा नहीं करेगा। देश को क्या नुकसान है उस से फारेन एक्सचेंज में या और बातों में यह सरकार देख ले। तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि किसान को जो कीमत वह मांगेगा वह कीमत सरकार देगी या नहीं या जो कास्ट हुआ, इन्वेस्टमेंट हुआ वह कीमत देगी या नहीं ?

दूसरी बात कारखाने पर किसान गाडी ले जाता है वहां उस की लूट होती है, किसान की गाडी में अगर 30 मन गन्ना है तो तोल में 20 मन तोला जाता है और एक गाडी पर दस मन का हिसाब लगायें तो हजारों गाड़ियों पर कितना उस को यह लूटते होंगे ? नीचे चपरासी से लेकर ऊपर से ऊपर मैनेजर तक बैठे है, सरमायेदार बैठे हैं जो उस का हजारों मन गन्ना हर रोज हजम कर जाते हैं। तो इस की तरफ इन का ध्यान है या नहीं और अगर है तो क्या उपाय करेंगे ?

तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि यह ज्यादती क्यों की जाती है ? शहरों में सारी चीनी लोग खायें और देहात की तरफ चीनी का नामों निशान नहीं। मैं कहना चाहता हूं कि सेंटर की तरफ से जो चीनी का स्टाक रिलीज करते हैं उसमें 70 परसेंट और 75 परसेंट चीनी के लिए आप डाएरेक्ट करिए स्टेट गवर्नमेंट्स को कि वह देहात की तरफ डाइवर्ट की जाय। यह मिनिस्टर साहब करने के लिए तैयार हैं या नहीं ? आखीरी बात मैं कहना चाहूंगा कि जो मिलों के चारों तरफ का एरिया है दस या पन्द्रह मील का उस में जबर्दस्ती किसानों को नेश्कर मिलों को देना पड़ता है। उस के ऊपर अटैचमेंट किया जाता है। अगर नहीं देते हैं तो उस की फसल अटैच कर ली जाती है। यह विधान के खिलाफ है और यह ज्यादती किसान के साथ क्यों है ? मैं मिनिस्टर साहब से पूछना चाहता हूं कि इस तरह का डाका किसान की फसल के साथ सरकार डालने देगी या उस को रोकेगी ? उस का कोई इलाज सरकार के पास है या नहीं ?

Shri D. C. Sharma (Gurdaspur): Mr. Chairman, sugarcane policy has a four-fold objective. The question I want to ask is this. What is the mechanism for arriving at the price of sugarcane which should be remunerative to the farmer, which should be economical to the factory owner and which should be reasonable to the consumer? May I know how many times this mechanism of arriving at the formula of the price of sugarcane has been revised so far, and whether

the Government is going to revise it in the near future, so that the farmers, the consumers, the interests of the foreign exchange and the interests of the people who make sugar, khandsari and gur are properly coordinated?

Shri N. K. Somani (Nagpur): Sir, one of the main reasons that have led to the ruin of the sugar industry is the way in which the Government of India have been temporising on this matter. The low sugarcane price and not only the natural drought but the drought of timely and purposeful policies at the Government of India level have been mainly responsible for it. I charge that there are political considerations in this matter so that there is no regulation of the clandestine and illegitimate operators of gur and khandsari all over India to the detriment of the sugar industry just as the recent studied silence of the Government of India when not a single person of this brilliant galaxy of co-operators raised his voice against the black-mailing attitude of the Maharashtra co-operative sector when they withheld the supplies of sugar from the city of Greater Bombay for six weeks—not one of them raised their voice because there are political considerations, because the Chairman of the Maharashtra Pradesh Congress Committee is actively in it—he is the Chairman of the Maharashtra co-operative complex. I would like to ask the hon. Minister when he would rid himself and the Government of India of all political considerations and take a decision in a business like manner.

Shri D. N. Patodia (Jalore): The solution of the problem, in my opinion, lies in evolving a system which takes care of four principal objectives by which the farmer gets a fair price, the production that we get is the maximum, the subsidiary industries like distilleries get proper raw materials and it brings adequate revenue to the State. I believe that the main problem has arisen on account of only 30 per cent of the industry being controlled by prices; 70 per cent of the cane is being consumed by gur and khandsari in respect of which price of cane is not controlled. Therefore productivity has gone down, the revenue has gone down and the subsidiary industries are not getting the raw materials because the cane is diverted from sugar to khandsari. May I know, therefore, whether Government will take into account this particular factor of 70 per cent of the sweetening agents being not controlled and if the Government finds that 100 per cent control of the sweetening agents price is not possible, Government would give a serious thought to it that it must be 100 per cent decontrol by which sugar can be produced more, excise duty can be collected and we can feed our subsidiary industries so that we may not have to import industrial alcohol which we are doing this year!

Shri S. S. Kothari (Mandsaur): The scarcity of sugar is the direct consequence of the halting policy which has been followed by Government during all these years. Rather than go into details, I will just submit that the legitimate way out of the impasse is to have certain integrated measures. Certain hon. Members have suggested that sugar should be decontrolled. I would submit a corollary to it. It should be partially decontrolled. The rationing system in certain cities has to be continued and sugar has to be supplied to the rationing system by the mills despite decontrol. That means, it should be restricted de-control and modified to that extent.

Secondly, the sugar factories should be encouraged to develop their own cane farms. That is a very important point.

Now I come to the most important point, and that is the question. Would the Government agree to reduce excise duty on sugar?

Shri Ranga (Srikakulam): That is the most important thing.

Shri S. S. Kothari: Would the Government agree to reduce excise duty on sugar to enable the sugar industry to pay higher prices to the sugarcane cultivators? Finally, is it possible for the Government to enforce excise duty on khandsari and gur producers?

Shri Ranga: No, no.

Shri S. S. Kothari: In my opinion these four integrated measures are necessary Would the Government consider bringing in these four integrated measures?

Shri S. M. Banerjee (Kanpur): I would like to know whether the hon. Minister is aware that both the U.P. Government and the Bihar Government have recommended to the Central Government that the sugarcane price should be fixed at Rs. 3/- and, if so, whether the Government has taken any decision and, if not, whether they are likely to announce the decision during this session itself. I want to know whether they will come to a final decision and stop swinging between control and decontrol like this. Let them come to some final decision.

श्री श्रीचन्द गौयल (चण्डीगढ़) : सभापति महोदय आज सरकार की गलत नीतियों का यह परिणाम है कि उपभोक्ताओं और गन्ने के उत्पादकों को बली का बकरा इस लिए बनाया जा रहा है कि हमें विदेशी मुद्रा कमाने के लिए सबसिडाइज्ड रेटस पर चीनी दूसरे देशों को भेजनी पड़ती है उस के कारण आज हम दोनों का गला घोटा जा रहा है । मैं जनना चाहता हूं कि क्या सरकार अपनी नीति में परिवर्तन करेगी और विदेशी मुद्रा कमाने के लिये दूसरी वस्तुओं के लिए मंड़ियां तलाश करेगी तथा चीनी का निर्यात बन्द कर के गन्ने का निरख बढ़ायेगी तथा जो चीनी के उपभोक्ता हैं उन के लिये चीनी के भाव कम करने की नीति पर विचार करेगी ?

Shri Sheo Narain (Basti): Allow me to put a question, Sir.

Mr. Chairman: His name is neither in the list nor he has sent any chit to me. Still he is so impatient.

Shri Sheo Narain: We are maintaining the quorum here . . . (*Interruption*).

Shri S. Kandappan (Mettur): Sugarcane is a tropical crop. In the south which is more tropic, even with our best effort, we are able to get about 50 to 60 tonnes per acre whereas with the best efforts of the Central Government in the north, they are able to get only 15 to 20 tonnes per acre. I am really in sympathy with the sugarcane growers in the north. According to me, the issue varies with different regions and the Government has, of late, realised it. They have appointed a committee to go into the problem of sugarcane industries in the South and in Deccan. I have recently read in the papers that the committee has submitted its report. I would like to know from the hon. Minister about the recommendations of that committee and whether they are going to implement those recommendations.

श्री तुलसी दास जाधव (बारामती) : सभापति महोदय मैं यह पूछना चाहता हूं कि उत्पादक किसान की तरफ न देखते हुए दूसरे अनुत्पादकों की फिक्र सरकार हमेशा पहले से देखती है जिसेके कारण आज हर चीज का गन्ना, शक्कर, कपास— उत्पादन कम हो रहा है । काश्मेकार गन्ना गुड़ बनाने में इस्तैमाल करतेने लगे हैं ।

दूसरे लोग अपनी यूनियन (संघ) को ताकत से सरकार से झगड़ते हैं, उन से सरकार डरती है लेकिन जो प्रामाणिक तौर पर रात दिन मेहनत कर के देश को उत्पादन देते हैं, ऐसे किसानों के साथ सरकार नहीं चलना चाहती है । मैं यह कहना चाहता हूं कि अब तक सरकार रिकवरी में 9.4 बेस के लिये 2 रु० 12 पैसा देती थी, अब काश्तकारों की मांग है कि उस बेस को

8.4 माना जाय और जिस तरह 9.4 के ऊपर 0.1 के लिये डेढ़ पैसा देती थी, अब डेढ़ पैसे के बजाय 8.6 पैसा दिया जाये।

Mr. Chairman: The hon. Minister.

Shri V. Krishnamoorthi (Cuddalore): Sir, allow me to put a question.

Shri Sheo Narain: Sir, I also want to put a question.

Mr. Chairman: The rules do not allow it. I was quite lenient. I allowed even those who sent me chits during the course of the speech of Shri Prakash Vir Shastri. Kindly honour the procedure also.

Shri Sheo Narain rose—

Shri V. Krishnamoorthi: I will put a question after Shri Sheo Narain.

Mr. Chairman: Even his name is not there.

श्री शिवनारायण : सभापति महोदय मैं आपका बड़ा अनुगृहीत हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं इस गवर्नमेंट से कहना चाहता हूं।

सभापति महोदय : मैंने अवसर नहीं दिया है। आपका नाम नहीं है।

श्री शिवनारायण : तो फिर न पूछूं ?

सभापति महोदय : फिर किसी वक्त देख लेंगे।

Shri V. Krishnamoorthi rose—

Mr. Chairman: His name is not there.

The Minister may reply.

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde): I am thankful to the hon. Member, Shastriji, for raising this discussion because the hon. members in this House as well as the public outside are concerned over the supply of sugar. That is because there have been some difficulties in the supply of sugar during the last few months. Though the discussion has been very brief, a wide field has been covered; various aspects of the sugar policy have been referred to by the hon. members.....

Mr. Chairan: There are a number of questions which are not within the scope of the point raised by Shastriji and which are also not within his jurisdiction. I would, therefore, request the Minister to be brief and answer those questions which are within the cognizance of his Ministry.

Shri Annasahib Shinde: I shall be very brief. I will finish my reply within three or four minutes. I do not want to take the time of the House.

I was referring to the point that the observations made by the hon. members today on the floor of the House would be useful to us in formulating our policies. There has been a criticism that there has been some delay in announcing the Government's policy in regard to sugarcane and sugar, in general. I quite agree and concede that there has been some delay. But being a federal State, naturally we have to go through the consultation process; we have to consult the State Governments. We were awaiting their replies. We also consulted the Chief Ministers. Being an economic decision of considerable importance, we have to give a considerable thought to this matter. I am sure that, in the near future, the decision would be announced. I hope that it should be possible to announce the decision of the Government in the current session of the Parliament.

Mr. Shastri referred to some important aspects of the sugarcane problems and the sugar problems. He referred to the steep fall in acreages.

[Shri Annasahib Shinde]

The figures which he produced are true because they are also corroborated by the information which has been conveyed to us by the various State Governments. He particularly referred to the steep fall in the acreage in U.P. He tried to blame the Government that the Government did not formulate an appropriate policy and that was why there had been a steep fall in acreage. I do not at all agree with the contention of the hon. Member because the facts belie that contention. We pursued a very appropriate sugarcane price policy during the last few years and that is why, the cane acreages went on increasing. For instance, I may refer here to an observation of the Agricultural Prices Commission. They say:

> "Besides, over the period 1952-53 to 1964-65, the acreage under sugarcane in the country increased at the compound rate of 4.03% per annum while the corresponding increase under foodgrains was only 0.98%."

That means that the cane acreage increased at a faster rate than the acreage under foodgrains. This shows that the price policy with regard to cane was more advantageous to the farmers. That is why we thought that the cane acreage should not exceed 65 lakhs of acres by the end of the Fourth Five Year Plan, but in fact, in the year 1964-65 itself, we reached the figure of 67 lakh acres in the country. When we are passing through a very difficult situation, it would not be to our advantage to allow a considerable acreage of land to come under sugarcane cultivation. Of course, I do agree that the sugar industry is a very important industry and it comes next to the textile industry in our country and about a lakh and a quarter employees are employed in this industry and millions of our farmers depend on the sugar industry. I could see that unless we have an appropriate sugarcane price policy it will not be possible for us to ensure adequate supplies of cane to the sugar factories. All along, our approach has been to see that the sugarcane growers are paid a remunerative price, and I am quite sure that whatever the decision of the Government may be in detail, we shall see that a remunerative price is announced and by and large the sugarcane growers would be satisfied with the sugarcane price which will be announced by Government.

श्री तुलसी दास जाधव : कब करेंगे ?

Shri Annasahib Shinde: I have already referred to that.

Shri S. S. Kothari: What about decontrol, partial or complete?

Shri Annasahib Shinde: There have been various suggestions about decontrol, partial decontrol, restriction on Khandsari and jaggery etc. All these suggestions have been made by the various State Governments also. But the difficulties are inherent in the situation. For instance, one of the suggestions was that there should be a ban on movement of jaggery from the surplus States. The deficit States have their own difficulties and they say that if there is a ban on movement of jaggery then those deficit States where jaggery is not produced will have difficulties. All these factors will have to be taken into consideration.

Moreover, there are strong inflationary tendencies in the country which also have got to be borne in mind. We have been supplying sugar at controlled price to the vulnerable sections in the urban areas. If all of a sudden we decontrol sugar, it will affect those people and the cost of living index would also increase. So, we have to take all these factors into consideration.

I may submit that all the suggestions made by hon. Members will be

policy which will be formulated and announced by Government will be in the wider national interest and in the interest of the growers and consumers etc. I think I have dealt with all the points....

Shri Anantrao Patil: What about the allegation made by Shri N. K. Somani about the co-operative sector in Maharashtra?

Shri Annasahib Shinde: I need not go into those details. I would only refer to Shri Bedabrata Barua's point that sugar factories were....

Shri V. Krishnamoorthi: What about the report of the committee?

Shri Annasahib Shinde: The report is under active consideration. We are considering it.

Shri Randhir Singh: What about sugar to the villages where about 30 to 40 crores of people live?

Shri Annasahib Shinde: It is only recently that we had received that report. We shall examine that report in consultation with other Ministries and we shall come to a decision.

18.38 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the Clock on Thursday, August 3, 1967/Sravana 12, 1889 (Saka).